ૐકાર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
"માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા"
ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-4 अंक : 45

सहयोग शुल्क : रु. 1 / सितंबर : 2020

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

"नई शिक्षा नीति से साक्षरता के साथ-साथ जीवन विकास के स्तर में भी एक क्रांती आएगी..."

– संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

"नई शिक्षा नीति सिर्फ कोई सर्कुलर नहीं महायज्ञ है, जो नए देश की नींव रखेगा और एक सदी तैयार करेगा..."

– प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

''है अगर होंसला बुलंद तो होगी हर मुश्किल आसान''

कभी-कभी विकलांगता की वजह से इन्सान भीतर से हार जाता है। दिव्यांगता उन्हें अंदर तक जकजोरकर रख देती है। लेकिन हंमेशा एक बात याद रखे की ईश्वर एक हाथ से कुछ छीनता है तो दूसरे हाथ से बहुत कुछ देता भी है । बस जरुरत होती उस वक्त नजरियां बदलने की सकारात्मक सोच अपनाने की। अगर इन्सान के मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो उसके जीवन में लाख बाधाएँ सामने आये, फिर भी वह कामयाबी की ओर अग्रेसर होता जायेगा। इस समाज में आज भी बहुत ऐसे लोग है जो लाचार और बेबश है लेकिन अपनी लाचारी के बावजूद भी समाज के सामने वो यह प्रदर्शित करना चाहते है कि अगर होंसला बुलंद हो तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। इसलिए तो कहा गया है कि... ''सकारात्मक सोच और बुलंद होंसले से बिना पंखो के भी उड़ा जा सकता है।''

ईश्वर के बनाये हुए हर एक इन्सान में सब कुछ करने की काबेलियत है। इसलिए दिव्यांग होते हुए भी कभी अपनी क्षमता को कम मत समजिए... ईश्वर के द्वारा दी गई इस शारीरिक अक्षमता को चुनौती मानकर जीत हांसिल करना यही आपके जीवन का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते रहीए। आप वह सब कुछ पा सकेंगे जो आप चाहते हो...

''बुलंद होंसले व इरादे के स्वामी होते है दिव्यांग''

आप सभी को निवेदन है की इस पत्रिका के बारे में आपके प्रतिभाव हमें भेजिए। आपके द्वारा दिया गया सुझाव या विचार हम इस पत्रिका में प्रकाशित करेंगे।

पाठको से यह निवेदन है की ''दिव्यांग सेतु'' पत्रिका में प्रकाशित करने हेतु, आपके आसपास दिव्यांगजनो के अनुलक्ष में हुए कार्यक्रम या कोई दिव्यांग व्यक्ति की जानकारी का ब्यौरा भी आप हमें भेज सकते है।

आओ आप भी हमारे साथ दिव्यांगजनो के सेवाकार्य में हमारा साथ दे...

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

सितंबर : 2020, पृष्ठ संख्या : 16

वर्ष : 4 अंक : 45

✦ प्रेरणास्त्रोत और संपादक ✦

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

✦ सह-संपादक ✦

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

✦ संपर्क-सूत्र ✦

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

✦ मुद्रक ✦

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

नई शिक्षानीति-२०२० पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का राष्ट्र को संबोधन

★ भारत की राष्ट्रीय शिक्षानीति का लक्ष्य २१ वी सदी के भारत की नींव तैयार करना है...

– माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भारत सरकार द्वारा २९ जुलाई २०२० को नई शिक्षा नीति को घोषित किया गया। यह १९८६ में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद पहला बदलाव प्रदान करती है, ७ अगस्त २०२० के दिन नई शिक्षा नीति पर देश को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा की ये शिक्षा नीति देश के भविष्य और विकास के लिए लाभदायक साबित होगी । नई शिक्षा नीति देश को विकसित और सशक्त बनाने में सहायक होगी, साथ ही इसके लागु होते ही पढ़ाई को लेकर जो बोज छात्रों के कंधो पर सालो से है वह कम होगा। वहीं करीयर चयन को लेकर छात्रों में भेडचाल की संभावना कम होगी।

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा की "नई शिक्षा नीति सिर्फ सरक्युलर नहीं, नया भारत तैयार करने की नींव है।" उन्होंने यह भी कहा की ३४ साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया है। ऐसे में हर सवालों पर ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति बनाते समय क्रिएटिविटी, क्युरीओसीटी और कमीटमेंट मेकींग पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा की नई शिक्षा नीति से छात्र ग्लोबल स्टुडन्ट तो बनेंगे लेकिन अपने जड़ से जुड़े रहेंगे। इस दौरान उन्होंने "जड़ से जग तक" यह मंत्र दिया। उन्होंने कहा की, "लंबे समय से शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं होने की वजह से भेडचाल को प्रोत्साहन मिलने लगा था । डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनने की होड से शिक्षा को बाहर निकालना जरूरी था। हमारे युवाओ में क्रिटिकल और इनोवेटीव थींकींग का विकास जरूरी था।" पी.एम. मोदी ने ये भरोसा जताया की नई शिक्षा नीति से यह संभव हो सकेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह भी कहा की बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था खडी हो रही है । नए ग्लोबल स्टैंडर्ड तय हो रहे है । स्कुली करीकुलम व्यवस्था में बदलाव हुआ है। इसमें ध्यान रखा गया है की छात्र ग्लोबल स्टुडेन्ट तो बन लेकिन अपने जड़ से जुड़े रहे।

भाषा से जुड़े मामले पर उन्होंने कहा की इसमें कोई विवाद नहीं है की बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई जानेवाली भाषा एक ही होने की वजह से सीखने में आसानी होगी। उनका कहना था की... ''जहां तक संभव हो पांचवी तक ऐसा ही करने को कहा गया है। इससे बच्चों की नींव को काफी मजबूती मिलेगी।''

पी.एम. मोदी के मुताबिक अभी की शिक्षी व्यवस्था का जोर ''क्या सोचे'' पर रहा है, लेकिन नई शिक्षा नीति में जोर ''कैसे सोचे'' पर होगा। उन्होंने कहा, इस दौर में जानकारी और कंटेट की कोई कमी नहीं है। लेकिन जरूरी यह है की कौन सी जानकारी हांसिल करनी है, क्या पढ़ना है, शिक्षा नीति में लंबे-चौडे सिलेबस और ढेर सारी किताबों की जरूरत को कम किया जाये।

नई नीति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा की... ''छात्रों को जरूरतो का खयाल रखकर मल्टीपल एन्ट्री-एग्जिट का विकल्प दिया गया है। अब छात्रों को इसकी भी स्वतंत्रता होगी की अगर कोई छात्र कोई कोर्स को छोडकर कोई ओर कोर्स करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा की मल्टीपल एन्ट्री-एग्जिट क्रेडिट बैंक के जरिये हमने ये रास्ता चुना है। हमने वो रास्ता चुना है जहां एक व्यक्ति जीवनभर एक ही नौकरी में नहीं टीका रहेगा। हमारी शिक्षा समाज में महेनत मजदूरी करनेवालो से जुडी नहीं रही लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डिग्निटी ओफ लेबर पर भी काफी ध्यान दिया गया है।''

माननीय प्रधानमंत्री ने सशक्त समाज के लिए उच्च शिक्षण संस्थानो को सशक्त करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, ''इसके लिए 'ऑटोनॉमी' शब्द आ जाता है। ऑटोनॉमी को लेकर एक तबका सरकारी नियंत्रण का पक्षघर है, दूसरा तबका संस्थानों को ऑटोनॉमी देने की बात करता है। बहेतर रास्ता इन दोनों जातो के बीच से होकर निकलता है।'' पी.एम. मोदी के मुताबिक जो संस्थान बहेतर करता है, उन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। नई नीति में डिग्नीटी ओफ रीसर्च पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, 'शिक्षा नीति में शिक्षको की बड़ी भूमिका होगी। मेरा मानना है जब शिक्षक सिखेंगे तब ही राष्ट्र आगे बढ़ेगा।' राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिए हम सभी को एक साथ संकल्पबद्ध होकर काम करना है। नई शिक्षा नीति २१ वी सदी के भारत की बुनियाद तैयार करेगी।

नई शिक्षा नीति: मोदी ने समझाया मातृभाषा में पढ़ाई क्यों जरूरी?

National Education
Policy 2020

देश की नींव तैयार करेगी
नई शिक्षा नीति

PM NARENDRA MODI
ON NEW EDUCATION
POLICY 2020
Important Points

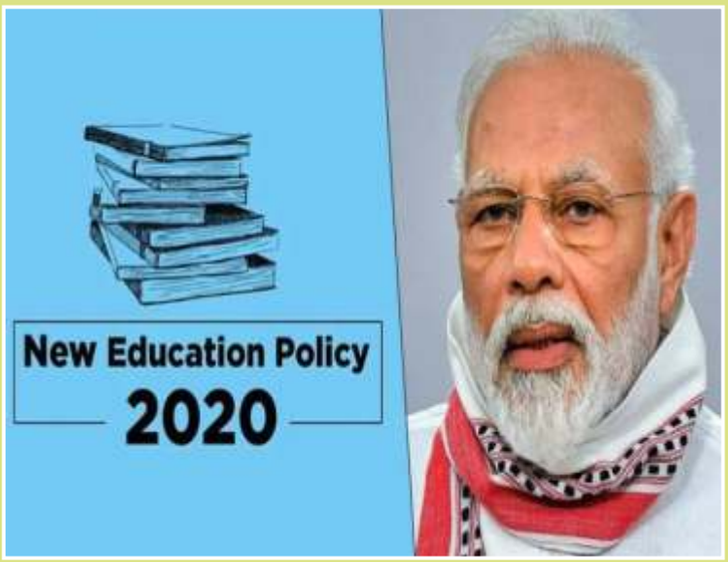
New Education Policy
2020

नई शिक्षा नीति – २०२० के प्रमुख परिवर्तन

नई शिक्षा नीति यानी न्यु एजुकेशन पोलिसी। नई शिक्षा नीति में क्या प्रमुख बदलाव हुए इसकी विस्तार से बात करने से पहेले यह जाने की इसे लाने की जरूरत क्यों पडी... ? इसके पीछे यह कहना है की बदलते वक्त की जरूरतो को पूरा करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, इनोवेशन और रीसर्च को बढ़ावा देने और देश को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की जरूरत है। अभी तक देश में जो शिक्षा नीति चल रही है, वो १९८६ में राजीव गांधी सरकार के दौरान लागु की गई थी और उसके बाद १९९२ में इसमें थोड़ा बदलाव किया गया था और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शिक्षा नीति में महत्त्वपूर्ण बदलाव किया गया। इस नई शिक्षा नीति के प्रमुख परिवर्तन की एक झलक ....

❖ मानव संशाधन विकास मंत्रालय अब 'शिक्षा मंत्रालय' :

मानव संशाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब एच.आर.डी. मंत्री को शिक्षामंत्री कहा जायेगा...

❖ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट होगा :

इसका मतलब यह है की मान लीजिए किसीने बी.टेक. में एडमिशन लिया है और दो सेमेस्टर के बाद उसका मन उचट गया कुछ ओर पढ़ने का तो उसका साल खराब नहीं होगा । एक साल के आधार पर सर्टीफीकेट मिलेगा और दो साल पढ़ने पर डिप्लोमा मिलेगा, कोर्स पूरा करने पर डिग्री मिलेगी। इस तरह की व्यवस्था होगी और कहीं और भी एडमीशन लेने के लिए रेकोर्ड कंसीडर किया जायेगा। इसे सरकार की पोलीसी में क्रेडिट ट्रांसफर कहा गया है। इसका मतलब है आपने कोर्स पूरा नहीं किया लेकिन जीतना किया उसका क्रेडिट मिल जायेगा आपको।

❖ ग्रेजुएशन :

नई शिक्षा नीति – २०२० में ग्रेजुएशन सिस्टम में भी बदलाव किया गया है। अभी **B.A., B.S.C.** जैसे ग्रेजुएशन कोर्स तीन साल के होते है। अब नई पोलीसी में इस तरह के विकल्प होंगे, जो नौकरी के लिहाज़ से पढ़ रहे है, उनके लिए तीन साल का ग्रेजुएशन और जो रीसर्च में

जाना चाहते है, उनके लिए चार साल का ग्रेजुएशन, फिर एक साल पोस्ट ग्रेजुएशन और चार साल का PHD । एमफील की जरूरत नहीं रहेगी । एमफील का कोर्स खत्म कर दिया गया है।

❖ मल्टीपल डिसटिलनरी एज्युकेशन होगी :

मल्टीपल डिसीप्लिनरी एजुकेशन यानी की कोई स्ट्रीम नहीं होगी । कोई भी मन चाहे सबजेक्ट चुन सकता है । यानी अगर कोई फिजिक्स में एजुकेशन कर रहा है और उसकी म्युज़िक में रुची है, तो म्युज़िक भी साथ में पढ़ सकता है । आर्ट्स और सायन्य वाला मामला अलग-अलग नहीं रखा जायेगा । हालांकी इसमें मेजर और माइनर सबजेक्ट की व्यवस्था होगी ।

→ कॉलेज को ग्रेटेड ऑटोनॉमी होगी । अभी एक युनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कई कॉलेज होते है, जिनकी परीक्षाएं युनिवर्सिटी कराती है । अब कॉलेज को भी स्वायत्ता दी जा सकेगी ।

→ उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेग्युलेटर बनाया जाएगा । जैसे अभी यु.जी.सी, ए.आई.सी.टी.इ जैसी कई संस्थाए हायर एजुकेशन के लिए है । अब सबको मिलाकर एक ही रेग्युलेटर बना दिया जाएगा । मेडीकल और लॉ की पढ़ाई के अलावा सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेग्युलेटर बॉडी "भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI)" का गठन किया जाएगा ।

→ नई शिक्षा नीति - २०२० का लक्ष्य व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में GER (सकल नामांकन अनुपात) को २६.३ प्रतिशत (२०१८) से बढाकर २०३५ तक ५० प्रतिशत करना है । GER हायर एजुकेशन में नामांकन मायने का एक माध्यम है । हायर एजुकेशन इन्स्टीट्युट्स में ३.५ करोड नई सीटें जोडी जाएगी ।

→ देशभर की हर युनिवर्सिटी के लिए शिक्षा के मानक एक समान होंगे । यानी सेंट्रल युनिवर्सिटी हो या स्टेट युनिवर्सिटी हो या डीम्ड युनिवर्सिटी सबका स्टैंडर्ड एक जैसा होगा । ऐसा नहीं होगा की बिहार के किसी युनिवर्सिटी में अलग तरह की पढ़ाई हो रही है और डीयु के कॉलेज में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है और कोई प्राइवेट कॉलेज भी अधिकतम फीस कितनी ले सकता है, इसके लिए भी फी कैप तय होगी ।

→ रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडींग के लिए अमेरिका की तर्ज पर "नेशनल रिसर्च फाउन्डेशन" बनाया जाएगा, जो सायन्स अलावा आर्ट्स के विषयो में भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा ।

→ **IIT, IIM** के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्व विद्यालय **(MERU)** स्थापित किये जाएंगे।

→ शिक्षा में टेक्नोलोजी के सही इस्तेमाल, शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंधन को कारगर बनाने तथा वंचित समूहों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रोद्यौगिकी मंच **(NETF)** बनाया जाएगा।

→ विश्व की टॉप युनिवर्सिटीस को देश में अपने कैंम्पस खोलने की अनुमति दी जाएगी।

❖ स्कुली शिक्षण में क्या होगा ?

उच्च शिक्षा की बात के बाद अब देखते है स्कुली शिक्षा में क्या बदलाव आएगा। यानी नर्सरी से लेकर १२ वी तक की शिक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन किया जाएगा।

→ अभी हमारा स्कुली सिस्टम १०+२ है यानी १० वी तक सारे विषय और ११ वी में स्ट्रीम तय करनी होती है। नई शिक्षा नीति में इसे बदलकर ५+३+३+४ किया गया है। इसमें स्कुल के आखिरी चार साल यानी ९ वी से लेकर १२ वी तक एक समान माना गया है, जिसमें विषय गहेराई में पढाये जाएंगे, लेकिन स्ट्रीम चुनने की जरूरत नहीं होगी मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी। फिज़ीक्स वाला छात्र चाहे तो हिस्ट्री भी पढ़ पायेगा। या कोई अेक्स्ट्रा करिकुलम एक्टीवीटी, जैसे म्युज़ीक या कोई गेम है, तो उसे भी विषय की तरह ही शामिल कर लिया जाएगा। ऐसी रूचिवाले विषयों को अेक्स्ट्रा नहीं माना जाएगा।

→ सभी बच्चे ३, ५ और ८ की स्कुली परीक्षा देंगे। ग्रेड १० और १२ के लिए बॉर्ड परीक्षा जारी रखी जाएगी,

लेकिन इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा । एक नया राष्ट्रीय आकलन केन्द्र 'परख' स्थापित किया जाएगा ।

→ ३ से ६ साल के बच्चों को अलग पाठ्यक्रम तय होगा, जिसमें उन्हें खेल के तरीको से सिखाया जाएगा । इसके लिए टीचर्स की भी ट्रेनींग होगी ।

→ कक्षा एक से तीन तक के बच्चो को यानी ६ से ९ साल के बच्चों को लिखना, पढ़ना आ जाए, इस पर खास जोर दिया जाएगा । इसके लिए "नेशनल मिशन" शुरु किया जाएगा ।

→ कक्षा ६ से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाये जाएंगे, यानी जिसमें बच्चे कोई स्किल सीख पाए । बाकायदा बच्चों की इन्टर्नशिप भी होगी, जिसमें वो किसी कारपेंटर के यहां हो सकती है या लॉन्ड्री की हो सकती है । इसके अलावा छठ्ठी क्लास से ही बच्चों की "प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग" होगी । कोडींग सिखाई जाएगी ।

→ स्कुलों के सिलेबस में भी नई शिक्षा नीति में बदलाव किया जाएगा । नये सिरे से पाठ्यक्रम तैयार किये जाएंगे और वो पुरे देश में एक जैसे होंगे । जोर इस पर दिया जाएगा की कम से कम पांचवी क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जा सके । किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी । भारतीय पारंपरीक भाषाए और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे । स्कुल में आने की उम्र से पहले बच्चों को क्या सिखाया जाए, यह भी माता-पिता को बताया जाएगा ।

→ प्रिस्कुल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा । स्कुल छोड चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कुल के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा । साथ ही नये शिक्षा केन्द्रो की स्थापना की जाएगी । नई शिक्षा नीति - २०२० के तहत स्कुल से दूर रह रहे लगभग २ करोड बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाने का लक्ष्य है ।

→ बॉर्ड की परीक्षाओं का अहमियत घटाने की बात है । साल में हो बार बॉर्ड की परीक्षाए कराई जा सकती है । बॉर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पेपर भी हो सकते है ।

→ बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में मुल्यांकन सिर्फ टीचर ही नहीं लिख पाएंगे । एक कॉलम में बच्चा खुद मुल्यांकन करेगा और एक में उसके सहपाठी मुल्यांकन करेंगे ।

→ स्कुल के बाद कॉलेज में दाखिले के लिए एक कोमन प्रवेश परीक्षा हो, इसके लिए "नेशनल एसेसमेंट

सेन्टर'' बनाये जाने की भी बात की गई है।

→ स्कुल से बच्चा निकलेगा, तो हर बच्चे के पास एक वॉकेशनल स्किल होगा।

→ **NCERT** की सलाह से, एनसीटीई टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक नया सिलेबस **NCFTE** २०२१ तैयार करेगा। २०३० तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता ४ वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी।

→ शिक्षको को प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया के जरीये भर्ती किया जाएगा। प्रमोशन योग्यता आधारित होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक **(NPST)** २०२२ तक विकसित किया जाएगा।

→ पढ़ने-लिखने और जोड़-घटाव (संख्यात्मक ज्ञान) की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति सही ढंग से सिखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए ''एनइपी **(NEP)** २०२०'' में मानव संसाधन विकास मंत्रालय **(MHRD)** द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक ''राष्ट्रीय मिशन'' की स्थापना कीये जाने पर विशेष जोर दिया गया है।

→ सामाजिक और आर्थिक नज़रीये से वंचित समुहो **(SEDG)** की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा।

→ नई शिक्षा नीति-२०२० में **GDP** का ६ प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य है जो अभी ४.४३ प्रतिशत है।

नई शिक्षा नीति-२०२० के इस प्रमुख परिवर्तन द्वारा कुल मिलाकर शिक्षा के जरीये २०३० तक १००% युवा और प्रौढ साक्षरता के लक्ष्य को हांसिल करना है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन **(IITI)**, राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानो में संस्कृत और सभी भाषा विभागो को मजबूत करने और ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानो के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रुप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा का प्रयोग करने की सिफारीश की गई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति - २०२० में छात्र, शिक्षा और श्रम की गरीमा पर बहुत व्यापक काम किया गया है और इसके लिए सभी को एक साथ संकल्पबद्ध होकर काम करना बेहद आवश्यक है....

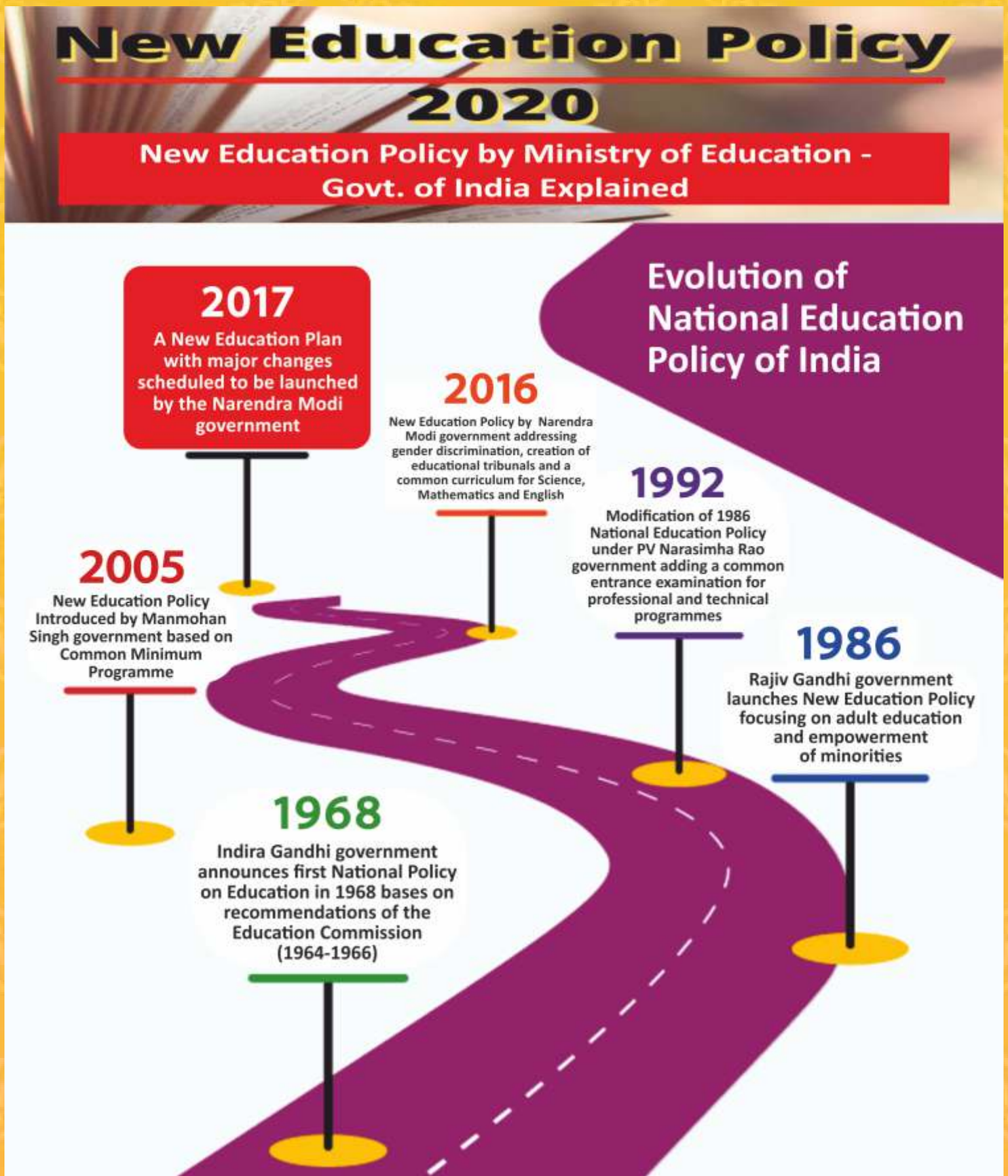
New Education Policy 2020
New Education Policy by Ministry of Education - Govt. of India Explained
Evolution of National Education Policy of India
2017
A New Education Plan with major changes scheduled to be launched by the Narendra Modi government
2016
New Education Policy by Narendra Modi government addressing gender discrimination, creation of educational tribunals and a common curriculum for Science, Mathematics and English
1992
Modification of 1986 National Education Policy under PV Narasimha Rao government adding a common entrance examination for professional and technical programmes
2005
New Education Policy Introduced by Manmohan Singh government based on Common Minimum Programme
1986
Rajiv Gandhi government launches New Education Policy focusing on adult education and empowerment of minorities
1968
Indira Gandhi government announces first National Policy on Education in 1968 bases on recommendations of the Education Commission (1964-1966)

आज सुबह १० से १२ बजे का ऑनलाइन सेशन होने के बाद नवजीवन चेरीटेबल ट्रस्ट संचालित 'डॉ. हरिकृष्ण डाह्याभाई स्वामी स्कूल फोर मेन्टली डिसेबल' के विद्यार्थीओं और उनके माता-पिता द्वारा दोपहर १२ से १ बजे तक जन्माष्टमी पर्व का उत्सव भजन-आनंद और गरबा के साथ मनाया था।

जिसमें स्कूल के अध्यापको ने संस्था में रहकर और छात्रों एवं उनके माता-पिताने घर पर रहकर ही ऑनलाइन भजन आनंद के साथे जन्माष्टमी पर्व का उत्सव मनाया था।

आज नवजीवन चेरीटेबल ट्रस्ट संचालित 'डॉ. हरिकृष्ण डाह्याभाई स्वामी स्कूल फोर मेन्टली डिसेबल' के विद्यार्थीओं के लिए ऑनलाइन रंगोली वर्कशोप का आयोजन किया गया था। जिसमें ३० से अधिक मनोदिव्यांग बच्चो ने उनके माता-पिता के साथ हिस्सा लिया था। बरोडा शहर के रंगोली विशेषज्ञ श्री मोना पटेल ने रंगोली बनाने की तालीम दी थी। स्कूल बंद होने के कारण संस्था के लाभार्थीओं को प्रवृत्तिमय रखने का हमारा प्रयत्न है। अलग-अलग प्रकार की रंगोली सिखा कर आनेवाली दिवाली पर्व की तैयारी कर रहे है, ऐसा कह सकते है।

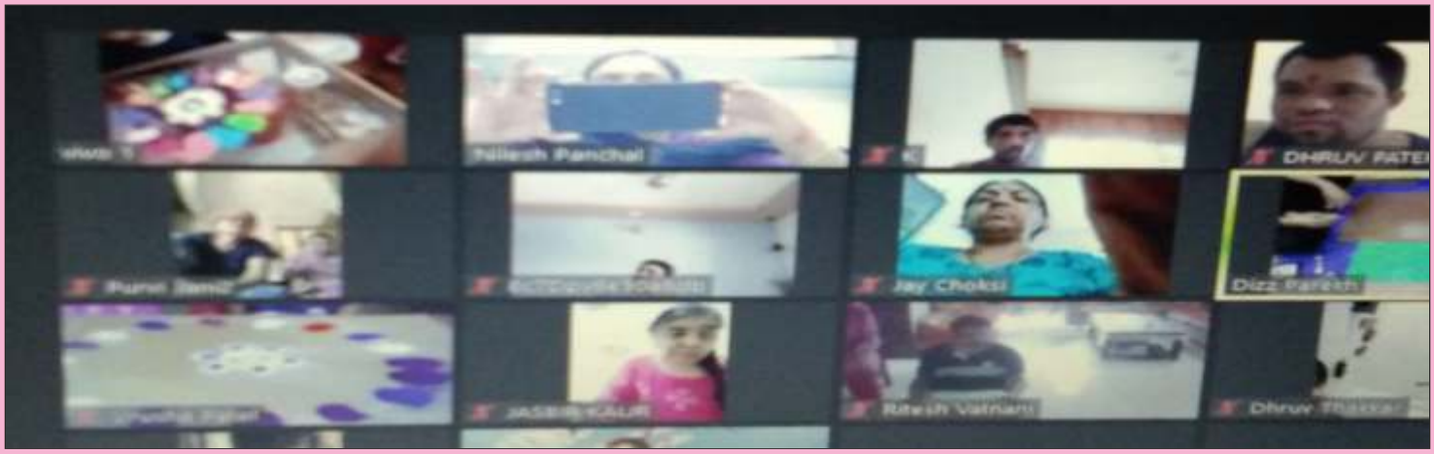

नवजीवन चेरीटेबल ट्रस्ट संचालित 'डॉ. हरिकृष्ण डाह्याभाई स्वामी स्कूल फोर मेन्टली डिसेबल' के मनोदिव्यांग विद्यार्थीओं के लिए ऑनलाइन शिक्षण-तालीम दी जा रही है। पीछले ४ महिनो से यह शिक्षण-तालीम विद्यार्थीओं को नियमित तौर से दी जा रही है। ऑनलाइन रंगोली वर्कशोप, डान्स वर्कशोप, आर्ट वर्कशोप, होम एक्टीवीटी, डेइली लीवींग एक्टीवीटी, एज्युकेशन इसले अलावा जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, स्वातंत्र्यदिन का त्योहार भी ऑनलाइन मनाया गया था। साथ में इस मास का गणेश चतुर्थी का उत्सव भी बड़े धूमधाम से ऑनलाइन मनाया गया था। गणेश चतुर्थी का उत्सव संस्था के मेनेजींग ट्रस्टी डॉ. आप्टे साहेब के घर पर मनाया गया था और वहां से लाइव टेलीकास्ट द्वारा मनोदिव्यांग बालको ने इस उत्सव में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया था।

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट
(N.G.O.)
संचालित
ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर
मानसिक दिव्यांग बच्चों के
लिए नि:शुल्क तालीमी संस्था
शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे
सुमेल ५, हाउस नं.: 48/डी, बिझनेश पार्क,
चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,
अहमदाबाद-380 016
मो. : 99749 55125, 99749 55365